कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जागृति

वर्ष : 66 अंक : 06 मुंबई मई 2022

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष : 66 अंक : 06 मुंबई मई 2022

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
संजीव पोसवाल

उप संपादक
सुबोध कुमार

डिजाईन व पृष्ठसज्जा

दिलिप पालकर
कलाकार

चंद्रशेखर पुनवटकर
कलाकार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई -400056 के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार 3 - 23

- खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया; भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ा
- केवीआईसी द्वारा "वाराणसी पश्मीना"का शुभारंभ
- केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार सृजन में जम्मू और कश्मीर को सभी भारतीय राज्यों में वरीयता दी
- अमेरिकी फैशन ब्रान्ड "पैटागोनिया" से खादी डेनिम के लिए दूसरी बार आर्डर मिलने से खादी की वैश्विक लोकप्रियता की पुष्टि हुई
- केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में पीएमईजीपी के तहत अब तक के सबसे अधिक रोजगार का सृजन कर, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े
- आयोग के अध्यक्ष ने आजीविका के उपकरण वितरित किए
- पीएमईजीपी सफलता की कहानी

प्रेस कवरेज व सोशल मीडिया 21-24

खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया; भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2022: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने एक उच्चतम महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जो भारत में सभी एफएमसीजी कंपनियां इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन को धन्यवाद देते हुए केवीआईसी ने पहली बार 1.15 लाख करोड़ रुपये का जबरदस्त कारोबार किया है, जो देश में किसी भी एफएमसीजी कंपनी द्वारा अभूतपूर्व है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली केवीआईसी देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, केवीआईसी का कुल कारोबार पिछले वर्ष यानी 2020-21 में 95,741.74 करोड़ रुपये की तुलना में 1,15,415.22 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार केवीआईसी ने वर्ष 2020-21 से 20.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और वर्ष 2014-15 की तुलना में 2021-22 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 172 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान सकल बिक्री में 248 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। केवीआईसी ने इस व्यापक कारोबार लक्ष्य को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण पहले 3 महीनों में यानी 2021 में अप्रैल से जून तक देश में आंशिक लॉकडाउन के बावजूद हासिल किया है।

पिछले एक वर्ष के प्रदर्शन को देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि खादी क्षेत्र पर देखी जा सकती है, जिसने 2020-21 में 3528 करोड़ रुपये से 43.20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और 2021-22 में यह 5052 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले 8 वर्षों में, यानी 2014-15 से 2021-22 में खादी क्षेत्र में उत्पादन में 191 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि खादी की बिक्री में 332 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, अकेले ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारोबार

(शेष पृष्ठ 17 पर....)

जागृति
खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वपोषण और शिल्प सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए

केवीआईसी द्वारा "वाराणसी पश्मीना" का शुभारंभ

वाराणसी, 08 अप्रैल, 2022: लेह लद्दाख हिमालय की ऊंचाइयों से वाराणसी में गंगा नदी के तटों तक पश्मीना शिल्प विरासत को नई ब्रांड पहचान मिली है।

वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों द्वारा तैयार किए गए पश्मीना उत्पादों को वाराणसी में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया। यह पहला अवसर है जब पश्मीना उत्पाद लेह-लद्दाख क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर से बाहर तैयार किए जा रहे हैं। केवीआईसी अपने शोरूमों, दुकानों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से "मेड इन वाराणसी" पश्मीना उत्पादों की बिक्री करेगा।

पश्मीना आवश्यक कश्मीरी कला के रूप में विख्यात है, लेकिन देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में फिर से इसकी खोज अनेक दृष्टि से अनूठी है। वाराणसी में तैयार

(शेष पृष्ठ 16 पर....)

केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार सृजन में जम्मू और कश्मीर को सभी भारतीय राज्यों में वरीयता दी

जम्मू, 21 अप्रैल, 2022: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास व रोजगार में तेजी के सुनहरे अध्याय की पटकथा लिखी है। वर्ष 2021-22 में केवीआईसी ने जम्मू और कश्मीर में अपनी प्रमुख योजना - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सबसे अधिक विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की, जो भारत में अन्य सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक है। जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड 21,640 विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की गई जो उत्तर प्रदेश (12,594 इकाइयों), मध्य प्रदेश (8082 इकाइयों), तमिलनाडु (5972 इकाइयों), कर्नाटक (5877) और गुजरात (4140 इकाइयों) जैसे बड़े राज्यों से काफी आगे है। पीएमईजीपी के तहत 2021-22 में अकेले जम्मू-कश्मीर में 1.73 लाख नए रोजगारों का सृजन किया गया जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा हैं।

2021-22 में केवीआईसी ने जम्मू-कश्मीर में 3,360 पीएमईजीपी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन स्थानीय विनिर्माण को लेकर केंद्र के प्रोत्साहन से उत्साहित होकर इसने 21,640 इकाइयों की स्थापना की। इस प्रकार लक्ष्य से 544 प्रतिशत से ज्यादा हासिल किया गया। जम्मू-कश्मीर में कुल 2101 करोड़ रुपये की पूंजी से इन इकाइयों की स्थापना की गई है। इसमें से केवीआईसी ने 467 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जबकि

बैंक क्रेडिट प्रवाह (बैंक द्वारा उधार दी गयी राशि) 1634 करोड़ रुपये था। केवीआईसी द्वारा जम्मू-कश्मीर में वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी भी देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने रोजगार सृजन में हुई भारी बढ़ोतरी व जम्मू और कश्मीर के सर्वांगीण विकास व आत्मनिर्भरता का श्रेय प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर स्वरोजगार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और विकास के मामले में इसे अन्य राज्यों के बराबर लाने की दिशा में केवीआईसी का बड़ा योगदान है। जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड पीएमईजीपी इकाइयों की संख्या इस बात का भी प्रमाण है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकारी योजनाओं में रुचि ले रहे हैं।

यहां यह बताना प्रासंगिक है कि जम्मू-कश्मीर का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य फोकस एरिया रहा है। 2014-15 से राज्य में स्थानीय रोजगार के सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। 2019 के बाद से प्रयासों को और मजबूत किया गया जब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।

पीएमईजीपी को वर्ष 2008 में शुरू किया गया और अगले 6 वर्ष यानी 2013-14 तक यह योजना जम्मू-कश्मीर में धीमी गति से आगे बढ़ी। हालांकि 2014-15 के बाद राज्य में पीएमईजीपी के तहत अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि केवीआईसी ने 6 वर्षों (2008-09 से 2013-14) में जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 10,401 पीएमईजीपी इकाइयां स्थापित की थीं, जबकि केवीआईसी द्वारा पिछले 8 वर्षों में 2014-15 से 2021-22 तक बड़े पैमाने पर 52,116 इकाइयां स्थापित की गईं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में केवीआईसी द्वारा 6 वर्षों (2008-09 से 2013-14) में वितरित की गई कुल मार्जिन मनी सब्सिडी केवल 145 करोड़ रुपये थी जबकि केवीआईसी ने पिछले 8 वर्षों (2014-15 से 2021-22) में मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 1080 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि का वितरण किया। इसके अलावा केवीआईसी ने पहले छह वर्षों (2008-09 से 2013-14) में पीएमईजीपी के तहत कुल 85,719 रोजगार सृजित किए जबकि पिछले 8 वर्षों में पीएमईजीपी के तहत जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर 4.10 लाख रोजगार का सृजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में पीएमईजीपी की अधिकांश इकाइयां बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और डोडा जैसे जिलों में स्थापित की गई हैं, जो बड़े पैमाने पर आतंकवाद से ग्रस्त हैं।

जम्मू-कश्मीर में 21,640 पीएमईजीपी इकाइयों में से 16807 (78 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कढ़ाई, मोबाइल/कंप्यूटर की मरम्मत की दुकानें, भोजन के आउटलेट आदि जैसी इकाइयों से संबंधित हैं। इसके बाद 1933 इकाइयां (9 प्रतिशत) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे स्टील फैब्रिकेशन व स्टील फर्नीचर, कृत्रिम आभूषण निर्माण, वर्मी-कम्पोस्ट और जैव-उर्वरक इकाइयों से संबंधित हैं। इसके साथ ही 1770 इकाइयां (8 प्रतिशत) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं।

अमेरिकी फैशन ब्रान्ड "पैटागोनिया" से खादी डेनिम के लिए दूसरी बार आर्डर मिलने से खादी की वैश्विक लोकप्रियता की पुष्टि हुई

प्रविष्टि तिथि: 14 APR 2022 2:42PM by PIB Delhi

अमेरिका के फैशन ब्रान्ड पैटागोनिया ने खादी डेनिम कपड़ा खरीदने के लिए एक बार फिर ऑर्डर दिया है। यह आदेश खादी के विश्वस्तरीय उत्पाद की गुणवत्ता तथा सप्लाई ऑर्डर पूरा करने में समयबद्धता के पालन की वैश्विक प्रशंसा है। पैटागोनिया ने इस वर्ष मार्च महीने में कपड़ा बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी अरविन्द मिल्स के माध्यम से गुजरात के राजकोट स्थित खादी संस्थान खादी भारती से लगभग 80 लाख रुपये मूल्य के 17,050 मीटर खादी डेनिम कपडा खरीदने का आदेश दिया। यह रिपीट ऑर्डर 1.08 करोड़ रुपये मूल्य के खादी डेनिम कपड़े के 30,000 मीटर के पिछले आदेश के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद मिला है।

जुलाई, 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पूरे विश्व में खादी डेनिम उत्पादों का व्यापार करने के लिए अरविन्द मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से अरविन्द मिल्स गुजरात के केवीआईसी द्वारा प्रमाणित खादी संस्थानों से प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में खादी डेनिम कपड़े खरीद रही है। इस नए आदेश के साथ पैटागोनिया द्वारा कुल खादी डेनिम की खरीद 1.88 करोड़ रुपये मूल्य के 47,000 मीटर हो गई है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि पैटागोनिया से रिपीट ऑर्डर खादी डेनिम की उत्कृष्ट गुणवत्ता, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाती है, के परिणामस्वरूप मिला है। उन्होंने कहा कि आदेश की आपूर्ति करते समय उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, उत्पाद की एकरूपता और कपड़े की समय से आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछला आदेश समय के अनुसार ठीक 12 महीने के समय में पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि खादी डेनिम के रिपीट ऑर्डर से इस बात की फिर पुष्टि होती है कि यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'लोकल टू ग्लोबल' का सटीक उदाहरण है।

खादी डेनिम कपड़े की खरीद गुजरात के खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त श्रम घंटे का सृजन कर रही है। सम्पूर्ण रूप से पैटागोनिया द्वारा खादी डेनिम की खरीद ने खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त 3 लाख श्रम घंटे का सृजन किया है।

अमेरिका स्थित फैशन ब्रांड पेटागोनिया ने गोंडल स्थित खादी संस्था- उद्योग भारती से 80 लाख रुपये मूल्य के 17,050 मीटर खादी डेनिम कपड़े खरीदने का दुबारा ऑर्डर दिया है।

यह रिपीट ऑर्डर 1.08 करोड़ रुपये के 30,000 मीटर खादी डेनिम फैब्रिक के पिछले ऑर्डर के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मार्च में, पेटागोनिया ने कपड़ा दिग्गज हाऊस अरविंद मिल्स के माध्यम से उस कपड़े को खरीदने का आदेश दिया, जिसका उपयोग पेटागोनिया डेनिम परिधान बनाने के लिए कर रहा है।

पिछले साल पैटागोनिया के एक दल ने खादी डेनिम की निर्माण प्रक्रिया देखने के लिए गोंडल, राजकोट (गुजरात) स्थित खादी संस्थान उद्योग भारती का दौरा किया था। खादी बनाने की प्रक्रिया तथा खादी डेनिम कपड़े की दस्तकारी गुणवत्ता से प्रभावित होकर पैटागोनिया ने अरविन्द मिल्स के माध्यम से विभिन्न मात्राओं में खादी डेनिम कपड़े खरीदने के आदेश दिए।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी डेनिम फैब्रिक के लिए फिर से प्राप्त आपूर्ति ऑर्डर की सराहना करते हुए कहा कि पेटागोनिया से रिपीट ऑर्डर खादी डेनिम "सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता" का परिणाम है।

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि पेटागोनिया से प्राप्त दुबारा ऑर्डर खादी डेनिम की "सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता" का परिणाम है।

अरविंद मिल्स लिमिटेड की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि पेटागोनिया, कंपनी की उपभोगता (क्लाइंट) है और मुख्य रूप से कंपनी से डेनिम खरीदती है। नवीनतम आदेश के साथ, पेटागोनिया द्वारा कुल खादी डेनिम खरीद लगभग 1.88 करोड़ रुपये मूल्य के 47,000 मीटर तक बढ़ गई है।

केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में पीएमईजीपी के तहत अब तक के सबसे अधिक रोजगार का सृजन कर, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के निष्पादन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के लिए वित्त वर्ष 2021-22 ऐतिहासिक कारनामों से भरा वर्ष रहा है। आयोग ने अभूतपूर्व रूप से 1.03 लाख नई विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की और 8.25 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया। इससे पीएमईजीपी वर्ष 2021-22 में सरकार के आत्म-स्थायित्व के सबसे शक्तिशाली उपाय के रूप में उभरा है, हालांकि देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान वर्ष के पहले 3 महीनों में आंशिक रूप से लॉकडाउन के अधीन था।

वर्ष 2008 में पीएमईजीपी योजना के शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब केवीआईसी ने एक वित्त वर्ष में एक लाख से अधिक नई इकाइयां स्थापित की हैं। ये 1,03,219 इकाइयां लगभग 12,000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी से स्थापित की गई हैं, जिसमें केवीआईसी ने 2,978 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की है, जबकि बैंक क्रेडिट प्रवाह लगभग 9,000 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में केवीआईसी द्वारा दी गई 2,978 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वर्ष 2008 से लेकर अब तक की ऐसी सबसे अधिक राशि है। पूरे देश में इससे 8,25,752 नए रोजगार सृजित हुए, जो पीएमईजीपी के तहत अब तक के सबसे अधिक रोजगार हैं।

पिछले वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में पीएमईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या और जुटाए गए रोजगारों की संख्या में 39-39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मार्जिन मनी वितरण (सब्सिडी) में भी वित्त वर्ष 2021-22 में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। .

व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014-15 से पीएमईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या में भी 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोजगार सृजन 131 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2021-22 में मार्जिन मनी वितरण में 165 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। .

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने रोजगार सृजन में हुई इस भारी बढ़ोतरी का श्रेय आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन को दिया है। इस बड़े प्रोत्साहन ने चमत्कार किया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विनिर्माण और स्वरोजगार के लिए यह एक बड़ा प्रोत्साहन है। पीएमईजीपी के तहत बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और प्रवासियों को स्वरोजगार गतिविधियां अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय और केवीआईसी के पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णयों ने भी इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को हासिल करने में सहायता प्रदान की।

हाल के वर्षों में केवीआईसी ने पीएमईजीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक पहल की हैं। वर्ष 2016 में केवीआईसी ने पीएमईजीपी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रस्तुत किया था। वर्ष 2016 से पहले आवेदनों को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किया जाता था। इससे प्रति वर्ष औसत रूप से केवल 70,000 आवेदन ही प्राप्त होते थे, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल स्थापित होने से प्रति वर्ष औसतन 4 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। ऑनलाइन प्रणाली से अधिक पारदर्शिता आई है। पीएमईजीपी पोर्टल ने आवेदकों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आवेदनों को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाया है।

एक अन्य प्रमुख कदम के रूप में केवीआईसी ने सभी पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग भी शुरू कर दी है ताकि किसी भी समय इन इकाइयों की भौतिक स्थिति और उनके प्रदर्शन को सत्यापित किया जा सके। अब तक 1 लाख से अधिक पीएमईजीपी इकाइयों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है। इससे कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप का उपयोग करके पीएमईजीपी इकाइयों का पता लगाने में सक्षम हो जाता है।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने केवीआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पीएमईजीपी परियोजनाओं को मंजूरी देने में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की भूमिका को समाप्त करके परियोजनाओं को मंजूरी देने और सीधे वित्त पोषक बैंकों को भेजने के लिए केवीआईसी ने राज्य निदेशकों को अधिकृत कर दिया है।

केवीआईसी ने अपने राज्य निदेशकों द्वारा आवेदनों की जांच और अग्रेषित करने की समय सीमा 90 दिन से घटाकर केवल 26 दिन कर दी है। इसके अलावा, बैंकों के साथ विभिन्न स्तरों पर मासिक समन्वय बैठकें शुरू की हैं, जिसके परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को समय पर ऋणों का वितरण किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में पीएमईजीपी के तहत अब तक के सबसे अधिक रोजगारों का सृजन

वर्ष	पीएमईजीपी के तहत केवीआईसी की वर्ष वार उपलब्धियां		
	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	वितरित की गई मार्जन मनी	रोजगार (संख्या)
2014-15	48,168	1122.54	3,57,502
2015-16	44,340	1020.06	3,23,362
2016-17	52,912	1280.94	4,07,840
2017-18	48,398	1312.4	3,87,184
2018-19	73,427	2070.00	5,87,416
2019-20	66,653	1950.81	5,33,224
2020-21	74,415	2188.78	5,95,320
2021-22	1,03,219	2977.61	8,25,752
कुल योग	5,11,532	13,923.14	40,17,600
2020 - 21 से प्रतिशत वृद्धि	39%	36%	39%
2014 -15 से प्रतिशत वृद्धि	114%	165%	131%

20 अप्रैल 2022 को माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजघाट स्थित केवीआईसी कार्यालय का दौरा किया और उद्यमशीलता प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के केवीआईसी के प्रयासों की सराहना की।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने
29 मार्च, 2022 को कानपुर और जालौन जिलों के कारीगरों को
विद्युत चालित कुम्हारी चाक और लेदर टूलकिट वितरित किए।
जिससे 900 स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे और
हमारे चर्म उत्पाद के कारीगरों को
"चर्म चिकित्सक" के सम्मानजनक नाम के साथ
एक सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया जाएगा।

आयोग के अध्यक्ष ने आजीविका के उपकरण वितरित किए

असम में बारपेटा और बजली जिलों की 40 बीपीएल महिला कुम्हारों ने 20 अप्रैल, 2022 को केवीआईसी की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इन कुम्हारों को स्थायी आजीविका के लिए प्रशिक्षण, विद्युत चालित कुम्हारी चाक और बाजार मंच प्रदान किया गया है।

मधुमक्खी बाक्सों एवं अन्य उपकरणों का वितरण

दिनांक 30.03.2022 को आयोग के मण्डलीय कार्यालय, विज़ाग द्वारा स्वयं सहायता समूह के 20 सदस्यों को हनी मिशन कार्यक्रम के

तहत मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बॉक्सों एवं अन्य उपकरणों का का वितरण किए गये। इस अवसर पर आयोग के मण्डलीय निदेशक प्रभारी, विज़ाग श्री एस रघु, आईटीडीए के अपर कार्यक्रम निदेशक, श्री नागेश्वर राव, बागवानी विभाग के सहायक निदेशक श्री दुर्गेश तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती श्रीवाणी कार्यक्रम में उपस्थिति थे।

आयोग के गजानन नाईक उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा एस.एन. कॉलेज, भायंदर, जिला-ठाणे के छात्रों के लिए एक दिवसीय उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी ने 02 अप्रैल, 2022 को ग्राम- महमूदपुर, चोलापुर, वाराणसी में 04 स्वयं सहायता समूह के 50 प्रशिक्षित लाभार्थियों के बीच विद्युत चालित कुम्हारी चाक, क्ले ब्लंजर मशीन और प्रमाण पत्र वितरित किए ।

नीति आयोग के दल ने 14 अप्रैल, 2022 को इलाहाबाद के निकट होलागढ़ हैंड एम्ब्रॉयडरी स्फूर्ति क्लस्टर का दौरा किया।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा 31.03.2022 को ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत गाजीपुर जिले के चर्म शिल्प कारीगरों को क्रैश कोर्स प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें 50 फुटवियर रिपेयरिंग टूल किट बॉक्स वितरित किए गये।

नीति आयोग के दल ने हैंड नॉटेड स्फूर्ति क्लस्टर इलाहाबाद का दौरा किया और कारीगरों के साथ बातचीत की।

(पृष्ठ 4 से आगे....)

खादी ने 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया; भारत में.....

पश्मीना इस विरासती कला को क्षेत्रीय सीमा से मुक्त करता है और लेह-लद्दाख, दिल्ली तथा वाराणसी की विविध कारीगरी का मेल करता है। वाराणसी में बुनकरों द्वारा तैयार पहले दो पश्मीना शॉल को वाराणसी में पश्मीना उत्पादों के औपचारिक लॉन्च से पहले केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 4 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किए गए।

वाराणसी में पश्मीना उत्पादन की यह यात्रा लद्दाख से कच्ची पश्मीना ऊन के संग्रह से प्रारंभ होती है। इसे डी-हेयरिंग, सफाई और प्रसंस्करण के लिए दिल्ली लाया जाता है। प्रसंस्कृत ऊन को रोविंग रूप में वापस लेह लाया जाता है जहां केवीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक चरखों पर महिला खादी शिल्पियों दवारा इसे सूत का रूप दिया जाता है। यह तैयार सूत फिर वाराणसी भेजा जाता है जहां इसे प्रशिक्षित खादी बुनकरों द्वारा अंतिम पश्मीना उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रामाणिकता और अपनत्व की निशानी के रूप में वाराणसी के बुनकरों द्वारा तैयार पश्मीना उत्पादों पर बुनकरों के नाम और वाराणसी शहर के नाम को अंकित किया जाएगा।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी में तैयार पश्मीना उत्पाद से ही वाराणसी में खादी की कुल बिक्री में लगभग 25 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे।

वाराणसी में पश्मीना की फिर से खोज करने के पीछे विचार लद्दाख में महिलाओं के लिए रोजगार के सतत अवसर पैदा करना और वाराणसी में पारंपरिक बुनकरों के कौशल को विविध रूप देना है। ऐसी ही परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। विशेष स्थिति में वाराणसी में पश्मीना बुनकरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। यह दस्तकारों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। सामान्य ऊन के शॉल की बुनाई के लिए बुनकरों को 800 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि पश्मीना शॉल बनाने के लिए वाराणसी में पश्मीना बुनकरों को 1300 रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वाराणसी में पश्मीना बुनाई से लेह-लद्दाख की महिला दस्तकारों के लिए पूरे वर्ष की आजीविका सुनिश्चित होगी। अत्यधिक सर्दी के कारण लगभग आधे वर्ष तक लेह-लद्दाख में कताई का काम बंद रहता है। इसमें सहायता देने के लिए केवीआईसी ने लेह में पश्मीना ऊन प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की है।

वाराणसी में पश्मीना बुनाई का कार्य 4 खादी संस्थानों- कृषक ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी, श्रीमहादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान गाजीपुर, खादी कम्बल उद्योग संस्थान गाजीपुर और ग्राम सेवा आश्रम गाजीपुर- द्वारा किया जा रहा है।

यूएस फैशन ब्रांड ने खादी डेनिम कपड़े के लिए केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना से खादी डेनिम कपड़े के लिए बार-बार ऑर्डर दिया, विकास की सराहना करते हुए कहा कि पेटागोनिया से रिपीट ऑर्डर खादी की डेनिम की "सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता" का परिणाम था।

देहरादून में विद्युत चालित चाक वितरण

आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनाँक 4.04.2022 को ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत कुम्हारी सशक्तिकरण योजना के तहत 20 कुम्हार लाभार्थियो को विद्युत चालित चाक वितरण किया गया।

इस अवसर पर श्री शोभाराम प्रजापति उपाध्यक्ष/राज्यमंत्री माटीकला बोर्ड, उत्तराखण्ड तथा श्री राम नारायण, राज्य निदेशक प्रभारी, देहरादून उपस्थित थे।

(पृष्ठ 3 से आगे....)

केवीआईसी द्वारा "वाराणसी पश्मीना" का शुभारंभ.....

2021-22 में 1,10,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 92,214 करोड़ रुपये था। पिछले 8 वर्षों में, 2021-22 में ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में 172 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री में 245 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी के अभूतपूर्व विकास का श्रेय देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन को दिया। साथ ही, नवीन योजनाओं, रचनात्मक विपणन विचारों और विभिन्न मंत्रालयों के सक्रिय समर्थन ने भी हाल के वर्षों में खादी के विकास में इजाफा किया है। "स्वदेशी" और विशेष रूप से "खादी" को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की बार-बार अपील ने चमत्कार किया है। आज खादी देश की सभी एफएमसीजी कंपनियों से बहुत आगे है। नए वैज्ञानिक तरीकों को नियोजित करके और खादी की उत्पाद श्रृंखला में विविधता लाने से केवीआईसी ने इतनी बड़ी वृद्धि हासिल करने में सफल रही है, जिसकी बराबरी कोई अन्य एफएमसीजी कंपनी नहीं कर सकती।

विशेष रूप से, लोगों ने "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" के प्रधानमंत्री के आह्वान की उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। पिछले कुछ वर्षों में, केवीआईसी का मुख्य ध्यान कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने पर रहा है। आर्थिक संकट का सामना करते हुए, बड़ी संख्या में युवाओं ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को अपनाया जिससे ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई।

साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने प्रमुख स्टोर पर खादी की एकल-दिन की बिक्री भी 30 अक्टूबर 2021 को 1.29 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

पीएमईजीपी सफलता की कहानी @जम्मू और कश्मीर

फरीदा अख्तर
अन्ना का बुटीक: ट्रेंड सेटर

अनंतनाग जिले के दूरू क्षेत्र में ट्रेंड सेटर माने जाने वाले अन्ना के बुटीक की मालकिन 31 वर्षीय फरीदा अख्तर हैं।

''फरीदा ने कहा, "मुझे खुशी है कि मैं एक उद्यमी हूं, लेकिन यह मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने कई वर्षों तक एक स्थानीय दर्जी के अधीन काम किया, जिसने मुझे ड्रेसमेकिंग की मूल बातें सिखाई, लेकिन यह बिल्कुल पारंपरिक सिलाई थी, ड्रेसमेकिंग में उनके जुनून ने उन्हें विशेष रूप से इंटरनेट पर डिजाइनिंग से आगे सीखने के लिए प्रेरित किया।

फरीदा ने कहा, ''वह 4000 रुपये प्रति माह के मामूली वेतन पर दिन में नौ घंटे काम करती थी। "जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त सीख लिया है, मैंने ऋण विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। इंटरनेट पर सर्फिंग के दौरान, मुझे जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत पीएमईजीपी योजना के बारे में पता चला। उन्होनें, जिला अधिकारी, अनंतनाग से संपर्क किया और ऋण के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन डीएलटीएफसी को भेज दिया गया और उसके पक्ष में 7.50 लाख रुपये के ऋण को मंजूरी दी गई।

वर्तमान में वह प्रति माह 30,000 रुपये कमाती है और उन्होनें 5 लोगों को रोजगार दिया है। फरीदा ने कहा, "मेरे उत्पाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं और यहां तक कि विभिन्न गांवों के ग्राहक भी मुझसे मिलने आते हैं।" उन्होंने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में डिजाइनर सूट का चलन स्थापित किया है।

वज़ीरा अली
डॉक्ट्रज़ उत्पाद, रासायनिक डिटर्जेंट की एक इकाई: एक विरासत को सभांलते हुए

परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय के हिस्सों के बिखराव के बाद, 33 वर्षीय वज़ीरा अली की पहली पसंद समान प्रकृति का व्यवसाय स्थापित करना था, लेकिन अलग-अलग नाम से। अपने पति से प्रेरित और, जो प्रबंधन में डॉक्टरेट हैं, वज़ीरा ने इस व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा।

वज़ीरा ने कहा, "हमारे पास रासायनिक डिटर्जेंट का पारिवारिक स्वामित्व वाला व्यवसाय था और यह अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक व्यवसाय में विभाजन हो गया था। नुकसान से चिपके रहने के बजाय, हमने समान प्रकृति का एक स्वतंत्र उद्यम शुरू करने का विकल्प चुना, आज, वे अपनी डॉक्ट्रज़ प्रोडक्ट्स, जो कि कनेरा चदूरा, बडगाम में दो कनाल में फैली रासायनिक डिटर्जेंट की एक इकाई, की मालिक है।"

एक नया उद्यम शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन उनके पति की प्रेरणा और मार्गदर्शन ने इसे संभव बनाया।

वजीरा ने कहा, "मेरे पति ने मुझे जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और उसकी योजनाओं के बारे में बताया। हमने एक प्रस्ताव के साथ जिला अधिकारी, बडगाम से संपर्क किया और डॉक्ट्रज़ उत्पादों की स्थापना के लिए मेरे पक्ष में 25 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। अपने पति की विशेषज्ञता के साथ, हम गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन करते हैं, इसलिए यह इतना आसान नहीं था हमारे लिए बाजार में जगह बनाना।"

वजीरा अपने सफल व्यवसाय के लिए जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड वजीरा अली के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

18 अप्रैल 2022 : लेह के लिकिर गांव में केवीआईसी द्वारा सशक्त बनाए गए 100 कुम्हार परिवार आत्मनिर्भरता के सच्चे ध्वजवाहक हैं।

इन महिला कुम्हारों ने लद्दाख में विलुप्त होने के कगार से इस विरासत कला को पुर्नजीवित करने के साथ ही अपनी आजीविका के लिए इस पुरातन कुम्हारी कला को सफलतापूर्वक अपनाया है।

आयोग के अध्यक्ष ने 11 अप्रैल,2022 को वाराणसी के केसरीपुर का दौरा किया, जो केवीआईसी द्वारा सशक्त एक कुम्हार गांव है। आयोग के अध्यक्ष ने कुम्हारों को ग्रामीण सशक्तिकरण के एक प्रमुख उपकरण के रूप में कुम्हारी उद्योग को विकसित करने में मदद करने के लिए सभी प्रकार के समर्थन और उनके मुद्दों के त्वरित निदान का आश्वासन दिया।

प्रेस कवरेज

खादी को और भी खूबसूरत बना रही धागा तैयार करने से रंगने तक की कोशिश

Indore News:
शहर के बुनकर ने कपड़े को महीन करने का किया प्रयोग।

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। खादी को और भी खास बनाने का प्रयास शहर के बुनकर द्वारा किया जा रहा है। यह प्रयास खादी के परिधानों को रंगने और कपड़े के टैक्स्चर को लेकर किया जा रहा है, जिसके जरिए केवल कपड़े में ही बदलाव नहीं हो रहा बल्कि रोजगार के नए आयाम भी नजर आने लगे हैं। यह प्रयास शहर के बुनकर द्वारा किया जा रहा है। अपने इस प्रयोग का प्रदर्शन वे इन दिनों शहर में जारी खादी प्रदर्शनी में किया जा रहा है।

बुनकर जयेश सरोदे ने खादी के कपड़े की बुनाई से लेकर उसकी रंगाई तक की तकनीक में बदलाव किया है। वे बताते हैं कि सूत कताई के दौरान उन्होंने धागे को पतला करने पर ध्यान दिया। धागा पतला होने से उतने ही कपास में ज्यादा लंबा धागा तैयार हुआ और धागे के पतला होने से कपड़े की मोटाई और वजन में भी फर्क आया। इस तकनीक के बाद तैयार कपड़े के वजन में कमी आई। जो कुर्ता पहले करीब दो सौ ग्राम वजनी होता था इस तकनीक को अपनाने के बाद उसका वजन करीब 120 ग्राम तक रह गया। अब इसे 100 ग्राम तक लाने का प्रयास है।

इससे कपड़े की कीमत में अंतर नहीं आया लेकिन धागा महीन होने से कपड़े की बुनाई दोगुनी गति से होने लगी और निर्माण समय में करीब 40 प्रतिशत तक की कमी आई। इसके अलावा कपड़े की रंगत में भी बदलाव किया। अभी तक सूत से धागा बनने के बाद उसकी लच्छी बनाकर रंगा जाता था। लच्छी उलझे नहीं इसलिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उसकी गठान लगा दी जाती थी इससे नुकसान यह होता था कि गठान वाली भाग में अमूमन रंग कम चढ़ पाता था जिससे तैयार कपड़े में कहीं-कहीं रंग कम नजर आता था। इस समस्या को दूर करने के लिए लच्छी के बजाए धागे को बाबिन में लपेटकर रंगना शुरू किया ताकि पूरे धागे में समान रूप से रंग चढ़े।

Posted By: Sameer Deshpande

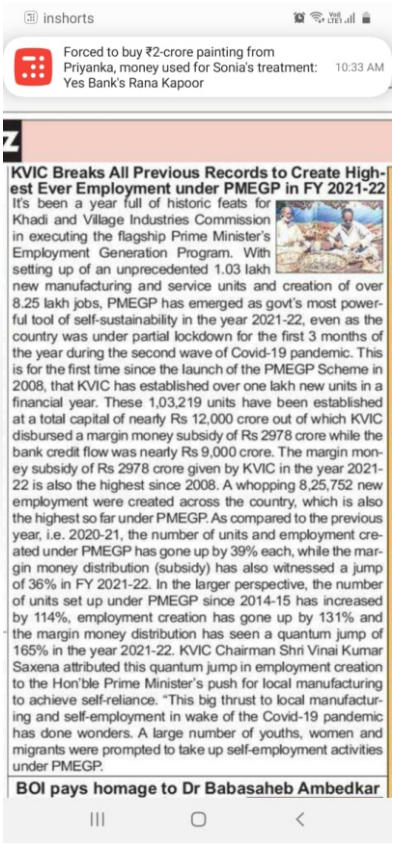

inshorts

Forced to buy ₹2-crore painting from Priyanka, money used for Sonia's treatment: Yes Bank's Rana Kapoor 10:33 AM

KVIC Breaks All Previous Records to Create Highest Ever Employment under PMEGP in FY 2021-22

It's been a year full of historic feats for Khadi and Village Industries Commission in executing the flagship Prime Minister's Employment Generation Program. With setting up of an unprecedented 1.03 lakh new manufacturing and service units and creation of over 8.25 lakh jobs, PMEGP has emerged as govt's most powerful tool of self-sustainability in the year 2021-22, even as the country was under partial lockdown for the first 3 months of the year during the second wave of Covid-19 pandemic. This is for the first time since the launch of the PMEGP Scheme in 2008, that KVIC has established over one lakh new units in a financial year. These 1,03,219 units have been established at a total capital of nearly Rs 12,000 crore out of which KVIC disbursed a margin money subsidy of Rs 2978 crore while the bank credit flow was nearly Rs 9,000 crore. The margin money subsidy of Rs 2978 crore given by KVIC in the year 2021-22 is also the highest since 2008. A whopping 8,25,752 new employment were created across the country, which is also the highest so far under PMEGP. As compared to the previous year, i.e. 2020-21, the number of units and employment created under PMEGP has gone up by 39% each, while the margin money distribution (subsidy) has also witnessed a jump of 36% in FY 2021-22. In the larger perspective, the number of units set up under PMEGP since 2014-15 has increased by 114%, employment creation has gone up by 131% and the margin money distribution has seen a quantum jump of 165% in the year 2021-22. KVIC Chairman Shri Vinai Kumar Saxena attributed this quantum jump in employment creation to the Hon'ble Prime Minister's push for local manufacturing to achieve self-reliance. "This big thrust to local manufacturing and self-employment in wake of the Covid-19 pandemic has done wonders. A large number of youths, women and migrants were prompted to take up self-employment activities under PMEGP.

BOI pays homage to Dr Babasaheb Ambedkar

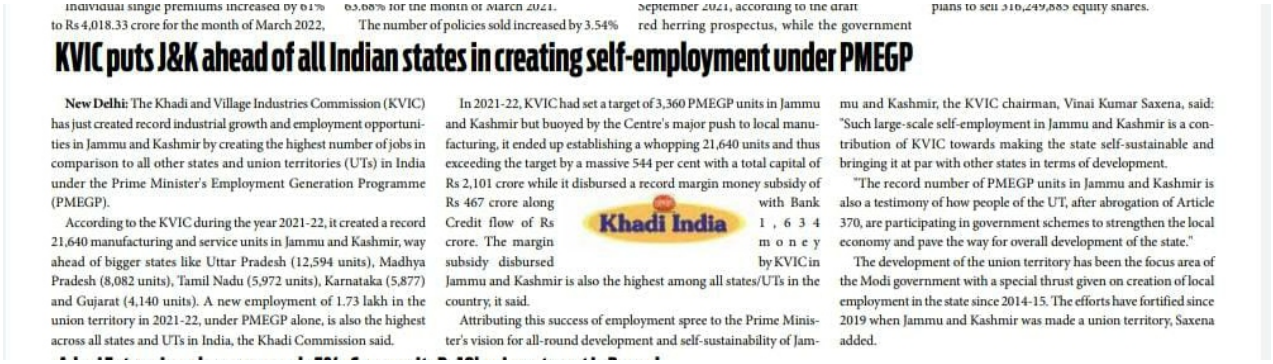

Individual single premiums increased by 61% to Rs 4,018.33 crore for the month of March 2022, 63.68% for the month of March 2021. The number of policies sold increased by 3.54% September 2021, according to the draft red herring prospectus, while the government plans to sell 316,249,885 equity shares.

KVIC puts J&K ahead of all Indian states in creating self-employment under PMEGP

New Delhi: The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has just created record industrial growth and employment opportunities in Jammu and Kashmir by creating the highest number of jobs in comparison to all other states and union territories (UTs) in India under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP).

According to the KVIC during the year 2021-22, it created a record 21,640 manufacturing and service units in Jammu and Kashmir, way ahead of bigger states like Uttar Pradesh (12,594 units), Madhya Pradesh (8,082 units), Tamil Nadu (5,972 units), Karnataka (5,877) and Gujarat (4,140 units). A new employment of 1.73 lakh in the union territory in 2021-22, under PMEGP alone, is also the highest across all states and UTs in India, the Khadi Commission said.

In 2021-22, KVIC had set a target of 3,360 PMEGP units in Jammu and Kashmir but buoyed by the Centre's major push to local manufacturing, it ended up establishing a whopping 21,640 units and thus exceeding the target by a massive 544 per cent with a total capital of Rs 2,101 crore while it disbursed a record margin money subsidy of Rs 467 crore along with Bank Credit flow of Rs 1,634 crore. The margin money subsidy disbursed by KVIC in Jammu and Kashmir is also the highest among all states/UTs in the country, it said.

Khadi India

Attributing this success of employment spree to the Prime Minister's vision for all-round development and self-sustainability of Jammu and Kashmir, the KVIC chairman, Vinai Kumar Saxena, said: "Such large-scale self-employment in Jammu and Kashmir is a contribution of KVIC towards making the state self-sustainable and bringing it at par with other states in terms of development.

"The record number of PMEGP units in Jammu and Kashmir is also a testimony of how people of the UT, after abrogation of Article 370, are participating in government schemes to strengthen the local economy and pave the way for overall development of the state."

The development of the union territory has been the focus area of the Modi government with a special thrust given on creation of local employment in the state since 2014-15. The efforts have fortified since 2019 when Jammu and Kashmir was made a union territory, Saxena added.

केवीआईसी सोशल मीडिया पर

फेसबुक व इंस्टाग्राम पोस्ट

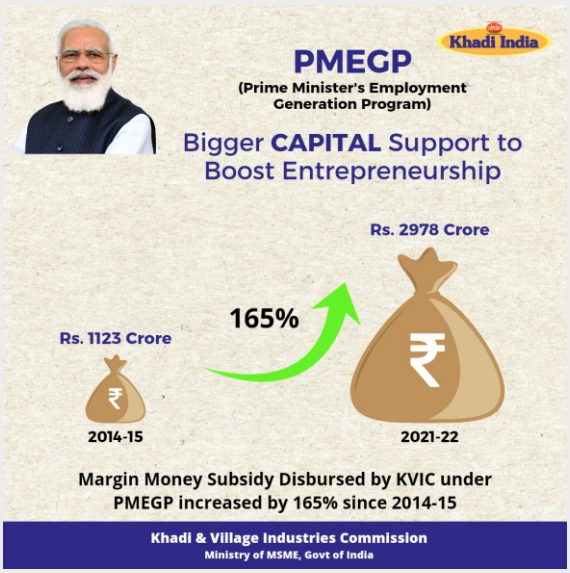

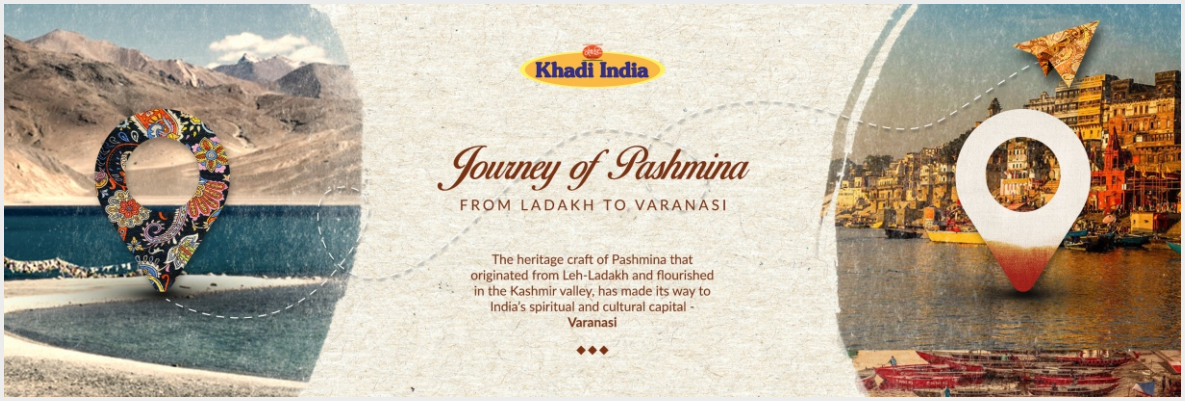

फेसबुक व इंस्टाग्राम पोस्ट

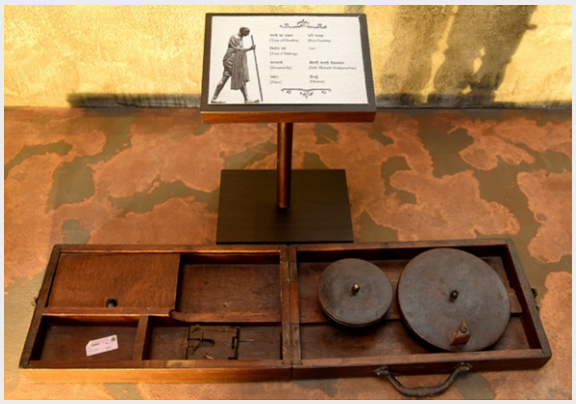

फेसबुक व इंस्टाग्राम पोस्ट

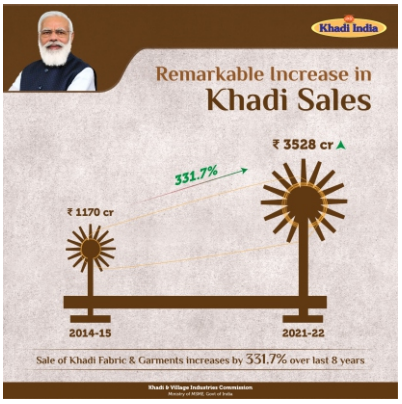

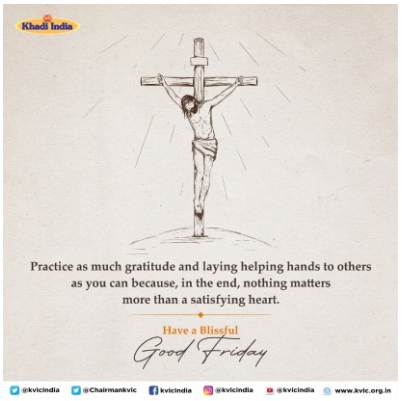

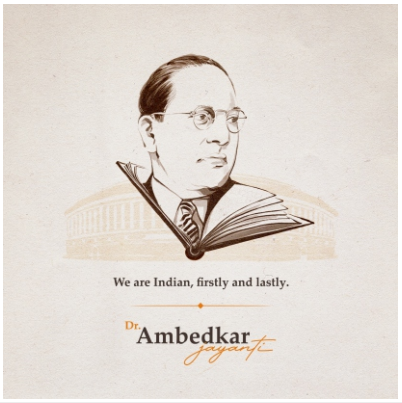

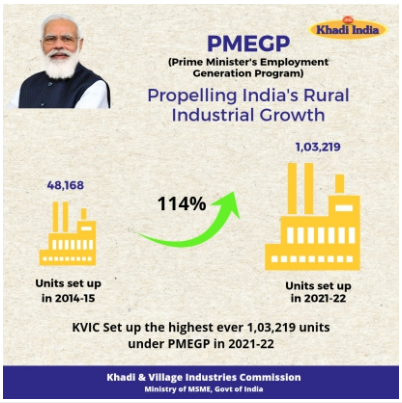

सत्यमेव जयते

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises,
Government of India.

Khadi India

हस्तनिर्मित

स्विट्ज़रलैंड से पेन और घड़ियाँ,
फ्रांस से चमड़े के जूते,
इटली से पर्स व बटुए और
मिस्त्र से कॉटन वस्त्र.

आप इन विदेशी वस्तुओं के लिए हजारों खर्च करते हैं और खरीदते हैं,
और जब भारतीय हस्तशिल्प खरीदने की बात आती है, आप संकोच करते हैं !

इस अवसर पर

अपने शहर के किसी खादी इण्डिया आउटलेट पर जाएं,
गर्व से खरीदें उच्च गुणवत्ता के हस्तनिर्मित वस्त्र और उत्पाद,
जो आपके देशवासियों द्वारा ग्रामीण भारत में बनाये गए हैं !

क्यों विदेशी हाथों को भुगतान करें ?

भारत की आत्मीयता को महसूस करें

KVIC ARTWING 2018

KVIC
कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
वेबसाइट : www.kvic.org.in

https://www.msme.gov.in | Follow us on minmsme @minmsme | Website: www.kvic.org.in | Follow us on kvicindia @kvicindia